

फार्मा निर्यात को मदद देगी सरकार

हैदराबाद/ नई दिल्ली, 5 अप्रैल. देश के औषधि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भारत की फार्मा राजधानी के रूप में विख्यात हैदराबाद में शनिवार को आयोजित एक चिंतन शिविर में केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने औषधि निर्यात क्षेत्र को सरकार की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के दुनिया के एक प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विख्यात हैदराबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्डोसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के सहयोग से किया गया. उद्घाटन सत्र की



अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने की और कार्यक्रम में फार्माएक्सिल के पदाधिकारियों और आमंत्रित सदस्यों के अलावा वाणिज्य और औषधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. वाणिज्य सचिव ने गुणवत्तापूर्ण और क्वाफायती दवाइयों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की रणनीतिक पुनर्संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता ही निर्णायक कारक बनी रहेगी. सचिव ने मूल्य, गुणवत्ता और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को

मजबूत करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और सत्र के दौरान निर्यातकों के साथ बातचीत करते हुए उनकी शंकाओं और चिंताओं का समाधान किया.

चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर दिये गये बल का उल्लेख किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा था शोधकर्ताओं और उद्यमियों को नई दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट प्राप्त करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत न केवल अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करे, बल्कि चिकित्सा आत्मनिर्भरता और नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बने, जिससे

वाणिज्य सचिव श्री अग्रवाल ने भारत के औषधि उद्योग की मजबूत विकास गति पर प्रकाश डाला और कहा कि विश्व की लगभग 18-19 प्रतिशत आबादी वाला भारत स्वयं एक विशाल और विस्तारित बाजार है, जहां बढ़ती आय स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को और बढ़ाएगी. वर्तमान में लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य वाले इस उद्योग में निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत योगदान है और यह अपने विशाल आकार, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और जेनैरिक दवाओं में वैश्विक नेतृत्व के कारण विश्व की फार्मसी के रूप में उभरा है.

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में देश की नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित हो.

अमूल ने पार किया 1 लाख करोड़ टर्नओवर का आंकड़ा

नई दिल्ली, 5 अप्रैल. भारत की डेयरी इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचते हुए अमूल ने वित्त वर्ष 2026 में 1 लाख करोड़ (1 ट्रिलियन) का टर्नओवर पार कर लिया है. यह उपलब्धि न केवल कंपनी की मजबूत ग्रोथ को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारतीय कोऑपरेटिव मॉडल अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है. लगभग 11प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ अमूल ने घरेलू बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत की है, वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कदम रखकर अपने विस्तार को नई दिशा दी है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नेतृत्व में संचालित अमूल की सफलता के पीछे उसका व्यापक वितरण नेटवर्क, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और किसानों से जुड़ा मजबूत आधार है.

लगातार चौथे साल महिंद्रा ईवी ने कायम रखा दबदबा

एमएलएमएमएल) ने वित्त वर्ष 2025-26में भी अपना मजबूत बाजार नेतृत्व बनाए रखा अब तक कुल मिलाकर 6 अरब से अधिक ई-किलोमीटरकी दूरी तय

मुंबई, 5 अप्रैल. भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (एमएलएमएमएल) ने वित्त वर्ष 2025-26में भी अपना मजबूत बाजार नेतृत्व बनाए रखा. कंपनी लगातारचौथे वित्त वर्षमें भारत की नंबर-1 इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माताबनी रही.

यह उपलब्धि उन हजारों चालकों और बेड़ा (फ्लीट) मालिकों के विश्वास का प्रमाण है, जिन्होंने अपने उद्यमिता के सफर

गोल्ड-सिल्वर में भारी गिरावट, निवेशकों को झटका

नई दिल्ली, 5 अप्रैल. पिछले एक महीने में सोने और चांदी की कीमतों में सोने और गिरावट ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है. जहां एक ओर सोना 26,000 से ज्यादा सस्ता हो गया है, वहीं चांदी के दामों में 36,000 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजार में बढ़ती अस्थिरता, युद्ध की स्थिति और डॉलर की मजबूती ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है. 5 मार्च 2026 को जहां सोना 1,60,586 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वह 2 अप्रैल तक गिरकर 1,46,608 पर आ गया.

चावल, गेहूं में साप्ताहिक गिरावट चीनी, खाद्य तेल मजबूत ; दालों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल. घरेलू थोक जिस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव गिर गये. गेहूं में भी नरमी रही. चीनी और खाद्य तेलों के भाव बढ़ गये जबकि दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया.

सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 27 रुपये टूटकर सप्ताहांत पर 3,825 रुपये प्रति किंटिल रह गयी. गेहूं 15 रुपये गिरकर 2,784 रुपये प्रति किंटिल बोला गया. आटा 17 रुपये सस्ता हुआ और 3,279 रुपये प्रति

रेपो दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान इकाई एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 5 अप्रैल. पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैठक में रेपो दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है. भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान इकाई एसबीआई रिसर्च की रिविार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही गयी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से पश्चिम एशिया संकट के रूप में दुनिया में एक बड़ा भू-राजनैतिक बदलाव आया है. विशेषकर हामुज जलदमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है. यह साल 1973 के बाद कच्चे तेल के बाजार में सबसे बड़ा व्यवधान है. रिपोर्ट के अनुसार, कच्चा तेल इस



समय 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है और रुपया 93 रुपये प्रति डॉलर से नीचे चल रहा है. साथ ही सुपर अल

नीनो प्रभाव की भविष्याणी की गयी है. इन सभी कारकों के मद्देनजर आरबीआई फिलहाल सावधानी बरतते हुए 08 अप्रैल को जारी होने वाले बयान में यथास्थिति बरकरार रखेगा. वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी संस्थान निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 16.6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी की जो 1991 के बाद सबसे ज्यादा है.

रुपया दबाव में है और 114 दिन में इसमें तीन रुपये प्रति डॉलर की गिरावट आ चुकी है. कच्चे तेल की कीमत ऊपर बनी हुई है . इन सबका समिलित परिणाम यह होगा कि अगली तीन तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत से अधिक रहेगी. मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल जून और अगस्त के बीच अल नीनो प्रभाव के सक्रिय रहने की 62 प्रतिशत संभावना जतायी है . साथ ही इस साल सुपर अल नीनो रहने की बात कही गयी है . इसका मतलब है कि तापमान दीर्घावधि औसत से दो डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहेगा . इससे भारत में मानसून प्रभावित होगा जिस पर आज भी ज्यादातर खरीफ की खेती निर्भर करती है .

आरबीआई की नीति से शेयर बाजार को दिशा मिलेगी

मुंबई, 5 अप्रैल. बीते सप्ताह गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में वैश्विक कारकों के साथ रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति संबंधी बयान से शेयर बाजार को दिशा मिलेगी. निवेशकों की नजर फिलहाल मुख्य रूप से ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट पर बनी हुई है.

इसका फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा. इससे निवेश धारणा कमजोर बनी हुई है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की गत 28 फरवरी को पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद पहली बैठक 06 अप्रैल को शुरू हो रही है. बैठक के फैसलों का भी बाजार पर असर दिखेगा. पिछले सप्ताह 31 मार्च को महावीर जयंती और 03 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवकाश के कारण बाजार में तीन दिन ही कारोबार हुआ. इसमें सोमवार को प्रमुख सूचकांकों में बढ़ी गिरावट रही जबकि बुधवार और गुरुवार को प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान कुल 263.67 अंक (0.36 प्रतिशत) टूटकर गुरुवार को 73,319.55 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 106.50



अंक यानी 0.47 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट के साथ 22,713.10 अंक पर रहा. मझौली कंपनियों का निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.82 प्रतिशत टूट गया . जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक लगभग अपरिवर्तित रहा. बीते सप्ताह सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयर टूट गए.

सनफार्मा में सबसे अधिक 5.62 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट रही. एनटीपीसी का शेयर 4.23 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट का 3.85, बजाज फिनसर्व का 3.18, भारती एयरटेल का 2.86, बजाज फाइनेंस का 2.13 और कोटक महिंद्रा बैंक का 2.13 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.. पावरग्रिड का शेयर 1.88 प्रतिशत, एशियन पेंट्स का 1.72 और आईसीआईसीआई बैंक का 1.47 प्रतिशत टूट गया. महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इटरनल, एक्सिस बैंक और हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर लाल निशान में रहे.

टेंट में सबसे अधिक 4.52 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गयी . बीईएल का शेयर 4.14 प्रतिशत, टेक महिंद्रा का 3.63, अडानी पोर्ट्स का 2.97, टाइटन का 2.92, एसीएसएल टेक्नोलॉजीज का 2.80 और टीसीएस का 2.59 प्रतिशत ऊपर रहा . इंफोसिस का शेयर 2.40 प्रतिशत, इंडिगो का 2.30, मारुति सुजुकी का 1.97 और एलएफटी का 1.34 प्रतिशत बढ़ा . टाटा स्टील में भी तेजी रही .

समाचार विशेष

सूची में के . अन्नामलाई का नाम क्यों नहीं ?



चेन्नई. भारतीय जनता पार्टी ने शुरुकार दोपहर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. इस लिस्ट की सबसे बड़ी चर्चा पार्टी के प्रमुख चेहरे के. अन्नामलाई का नाम न होने को लेकर रही, जिसने सभी को चौंका दिया.

बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल. मुरगन को अविनाशी सीट से मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई की मायलापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो बीजेपी को मिली इकलौती सीट है. इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेश्रान को सत्र से टिकट दिया गया है. वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी को श्रीनिवासन

सीट बंटवारे में दिखा बीजेपी का बड़ता प्रभाव

तमिलनाडु में सीटों का मौजूदा बंटवारा बीजेपी के सीमित लेकिन लगातार बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है . साल 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से उरई 4 सीटों पर जीत मिली थी . इस बार बीजेपी को 27 सीट मिली है जो उसके विस्तार की ओर इशारा करती है . कई जानकारों का मानना है कि इस बार सिर्फ सीटों की संख्या ही अहम नहीं है बल्कि राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में फेली सीटें ज्यादा महत्वपूर्ण है . यही फैक्टर भाजपा के अंदर जीत की उम्मीदों को मजबूती दे रहा है .

बंगाल चुनाव में पहाड़ों का ‘पंचकोणीय’ खेल



कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति जब मैदानों से निकलकर पहाड़ों की घुमावदार वादियों में पहुंचती है, तो वहां की फिजां और चुनावी समीकरण अगंभी पूर्ी तरह बदल जाते हैं. आगामी दिनों होने वाले विधानभा चुनावों के लिए राज्य की 294 सीटों पर बिसात बिछ चुकी है

दिलचस्प बात यह है कि जहां

क्या अजय एडवर्ड्स बिगाड़ देंगे दिग्गजों का सियासी गणित ?

राज्य की अधिकांश सीटों पर चार प्रमुख ताकतों के बीच मुकाबला सिमटा हुआ है, वहीं दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग जैसी ‘पहाड़ों की रानी’ कही जाने वाली सीटों पर इस बार ‘पंचकोणीय’ संघर्ष देखने को मिल रहा है. यह केवल पांच उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहाड़ों के भविष्य और पहचान की एक नई जंग है, जिसे हर दल अपने-अपने चरम से देख रहा है. मैदान की राजनीति से अलग पहाड़ों में इस बार नए समीकरण बन रहे हैं. पश्चिम बंगाल की अधिकांश सीटों पर मुकाबला

तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, वाम मोर्चा-एआईएसएफ गठबंधन और कांग्रेस के बीच सिमटा हुआ है. लेकिन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में प्रवेश करते ही यह चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. यहां की तीन महत्वपूर्ण सीटों- कुर्सियांग, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग पर चुनावी लड़ाई अब पंचकोणीय हो चुकी है. इन क्षेत्रों में भाजपा को बिमल गुरुंग के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का साथ मिला है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अर्जुन थापा के भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) पर भरोसा जताया है.

विशेष क्या महिलाएं पलट देंगी चुनावी बाजी ?

भाजपा को गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती

पुडुचेरी. पुडुचेरी की राजनीति में मन्नाडिपेट विधानसभा क्षेत्र का अपना एक खास महत्व रहा है. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब सिंघासी पारा चढ़ने लगा है. पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है और पांडिचेरी जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.

लगभग 39 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में मनालीपेट, चेट्टीपेट और सुथुकेनी जैसे इलाके शामिल हैं. मन्नाडिपेट की



जनता हमेशा से लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती आई है, जिसका अंदाजा यहां के पिछले मतदान प्रतिशत से लगाया जा सकता है.

इस निर्वाचन क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. साल 2021 के चुनावों में यहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जब भारतीय

जनता पार्टी के ए. नमशिवायम ने जीत का परचम लहराया था. उन्होंने डीएमके के ए. कृष्णन का 2,750 वोटों के अंतर से हराया था. उस समय भाजपा को यहां करीब 52.61 प्रतिशत वोट मिले थे. हालांकि, इससे पहले 2011 और 2016 के चुनावों में यहां एआईएनआरसी का दबदबा रहा था. यह देखना रोमांचक होगा कि क्या भाजपा अपनी पिछली जीत की लय को बरकरार रख पाती है या फिर क्षेत्रीय दल अपनी जीत हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होते हैं. मतदाताओं के मन में इस

महिला शक्ति तय करेगी मन्नाडिपेट का भविष्य

मन्नाडिपेट के चुनावी आंकड़ों का सबसे दिलचस्प पहलू यहां की महिला मतदाता है . 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की गई मतदाता सूची के अनुसार, यहां कुल 31,063 पंजीकृत मतदाता हैं . इनमें पुरुषों की संख्या 14,600 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 16,460 तक पहुंच गई है . यहां का लिंगानुपात 1127 है, जो स्पष्ट करता है कि जीत का रास्ता महिलाओं के समर्थन से ही होकर गुजरेगा . पिछले कई चुनावों से महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा प्रभावी रही है . ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सबसे बड़े चुनावी हथियार बन गए हैं .

बार विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर कई सवाल हैं . भाजपा के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती-सत्ताधारी दल के लिए मन्नाडिपेट की जंग इस बार असाधारण नहीं मानी जा रही है . 2021 में मिली जीत का अंतर लगभग 9.54

प्रतिशत था, जो पिछले चुनावों की तुलना में काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है . 2016 में तो जीत का अंतर महज 419 वोट ही था. आंकड़ों के इस खेल के बीच, आम मतदाता अब केवल पार्टी का चेहरा नहीं, बल्कि काम की रिपोर्ट देख रहा है .